Notifications Under Customs Act, 1961

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): I beg to lay on the Table

a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1961 :—

(1) G.S.R. 287 (E) published in Gazette of India dated the 30th March, 1983 together with an explanatory memorandum extending the validity of Notification No. 198-Customs dated the 2nd August, 1976 upto the 31st March, 1985.

(2) G.S.R. 293 (E) and 294 (E) published in Gazette of India dated the 31st March, 1983 together with an explanatory memorandum extending the validity of Notification No. 200-Customs dated the 28th September, 1979 and Notification No. 71/83-Customs dated the 1st March, 1983 up to the 30th June, 1983.

(3) G.S.R. 295 (E) and 296 (E) published in Gazette of India dated the 31st March, 1983 together with an explanatory memorandum extending the validity of Notification No. 179= Customs dated the the 22nd August, 1979 and Notification No. 2-Customs 1st January, 1979 dated upto the 30th June, 1983.

(4) G.S.R. 297 (E) published in Gazette of India dated the 31st March, 1983 together with an explanatory memorandum extending the validity of Notification No. 197-Customs dated the 14th October, 1978 upto the 31st March, 1984.

(5) G.S.R. 316 (E) published in Gazette of India dated the 5th April, 1983 together with an explanatory memorandum making certain amendment to Notification No. 241/82-Customs dated the 4th November, 1982 so as to rectify certain discrepancies in the latter notification.

(6) G.S.R. 318 (E) published in Gazette of India dated the 6th April, 1983 together with an explanatory memorandum regarding revised rate of exchange for conversion of Singapore Dollars into Indian Currency or *vice-versa* in supersession of Notification No. 92-Customs dated the 1st April, 1983.

(Placed in Library See No. LT-6356/83)

11.33 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

Fifty seventh Report

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North): Sir, I beg to present the Fifty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported declining trend in women's employment and retrenchment of women employees in several industries

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, मैं पटसन कपड़ा जैसे अनेक उद्योगों में महिलाओं के रोजगार की गिरती हुई स्थिति, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों समेत अनेक उद्योगों में महिला कर्मचारियों की छंटनी तथा महिलाओं के रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए अत्यन्त सीमित अवसर उपलब्ध होने के समाचार तथा इस स्थिति को सुधारने की अविलम्ब आवश्यकता की ओर श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

11.35 Hrs.

(*Mr. Duputy Speaker in the Chair*)

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): Government is aware of the apprehension expressed by some women's organisations about the unsatisfactory employment position of women. There was a definite increasing trend in women's employment, bet-

ween 1976 and 1978, in the organised manufacturing sectors, as a whole, based on the Employment Market Information Programme. In 1979, the level of employment was almost the same as in 1978. Though such level decreased to some extent in 1980, it was nevertheless higher than in 1976. At the level of the individual industry, a declining trend, of a small magnitude, was noticed only in the manufacture of wooden products, furn iture and fixtures and non-metallic mineral products Other industries recorded either a constant or an increasing trend.

2. The Central Government is concerned, as the appropriate Government, under the Industrial Disputes Act, 1947, with retrenchment of workers, as a whole, that is both men and women, in the Central sphere. The relevant statistics, relating of retrenchment of workers, does not, however, contain the break-up regarding men and women workers. In the State sector, it is the State Governments who are the appropriate authorites in regard to the industries falling in that sphere.

3. Comparison of the number of registration of women as against their placement effected by the Employment Exchanges, during the year 1978 to 1982, shows that the percentage of placement to registration of women applicants has more or less been constant at 7% as compared to 8% for men. This percentage by itsefl, does not reitect on the limited opporotunities for jobs for women, since many placements are made without the channel of Employment Ext changes.

4. Training facilites exist for both boys ana girls. Vocational training for boys and girls at the Craftsman level is done through a network of Industrial Training Institutes. Under this programme, training is provided in 32 Engineering and 26 non-engineering trades. There are at present 1084 Industrial Training Institutes out of which about 125 are exclusively for women providing them more than 4000 seats. Under the Apprentices Act, 1961, 3145 women were engaged as trade apprentices as on 28.2.1983 and 332 women engaged as graduate apprentices in February, 1983. As a measure of promoting women's vocational training facilites at the State levels, all those Governments have been requested to set up women's ITIs, through their own resources, as has been done by the Central Government in setting up the National Vocational Training Institute and two Regional Vocational Training Institutes for women.

5. The Equal Remuneration Act, 1976 was enacted, in order to give effect to the Constitutional provisions and the ratified ILO Convention No. 100. The Act provides for the payment of equal remuneration to men and women workers for the same work, or work, of a similar nature, and for the prevention of discrimination against women in matters of employment. Among other things, the act provides for the setting up of one or more Advisory Committees by the appropriate government, to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such establishments or employments as the central government may, by notification, specify in this behalf. A central advisory committee has accordingly been set up. Most of the State Governments/Union Territory Admintstrations have also set up Advisory Committees.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shrimati Usha Prakash Choudhari. I am not going to ring the bell, because all of you who are going to speak are going to be ladies today.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : If it is partiality towards women, we do not mind it.

MR. DEPUTY SPEAKER : Not that I am afraid of ladies, but I want to be chivalrous.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : It is the ladies day today.

MR. DEPUTY SPEAKER : Therefore, we will give them opportunity.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi) : Sir, you said you are not afraid of ladies. But that has to be decided by us, not by you.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आशा है सभी पुरुष सदस्य हमें इस में अनुमोदन देंगे ।

अभी-अभी हमारे मंत्री महोदय ने यहां हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया है। हम लोग आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। स्वतन्त्रता के बाद हमारे प्रजातन्त्र के सामने जो सब से बड़ी समस्या खड़ी हुई - वह बेरोजगारी की समस्या है, जिसे हम अभी तक हल नहीं कर पाये हैं। मैं एक ही उदाहरण पेश करना चाहती हूं। आज महिलाओं की ही बेरोजगारी की बात नहीं है, हमारे महाराष्ट्र के धूलिया डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल एक युवा कार्यकर्त्ता था। वह ग्रेजुएट हुआ था और सर्विस के लिए उसने काफी भागदौड़ की थी। जब उसको सर्विस नहीं मिली तो एक दिन गुस्से के मारे, समाज को बताने के लिए उसने अपना हाथ काट दिया। उसने कहा कि जिस हाथ से काम नहीं मिलता, जिस हाथ के लिए यह पढ़ाई, शिक्षा डिग्री और किसी काम की नहीं है, उसकी क्या जरूरत है। यह हालत है हमारे शिक्षित बेरोजगारों की। महिलाओं की बेरोजगारी की तो इससे भी बुरी हालत है।

हमारे यहां 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। जो राष्ट्र और समाज 50 प्रतिशत महिलाओं पर खड़ा है, उस समाज में और राष्ट्र में 50 प्रतिशत महिलाएं होने के बावजूद शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। हमारे यहां शिक्षा में पुरुषों का परिणाम 45.59 परसेंट है और महिलाओं का परिणाम 21.95 परसेंट है। यह तो शिक्षा की बात है। सेवा में हम महिलाओं को कितनी तरक्की देते हैं यह भी हम सबको मालूम है। हम अपने राष्ट्र को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने वाला राष्ट्र कहते हैं जहां कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी सेवा में नियुक्त किया जाता है। खेती से ले कर इंडस्ट्री तक सभी जगह उनको सेवा में नियुक्त किया जाता है। सेवा में उनके बल का उपयोग किया जाता है जो राष्ट्र सभी जगह महिलाओं को पूरा स्थान देता है वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है। लेकिन बड़े दुःख के साथ हम को कहना पड़ता है कि हमारे यहां पुरुषों का रोजगार में 57 प्रतिशत है और महिलाओं का कुल 28 प्रतिशत है। बाकी की महिलाएं बच्चों के पालन-पोषण, परिवार और समाज की सेवा से जुड़ी हुई हैं।

मंत्री महोदय ने रोजगार के बारे में अपने स्टेटमेंट में एक बात कुबूल की है कि महिलाओं में व्यवसाय और उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़ापन है। लेकिन मैं आपको आंकड़ों के आधार पर कहना चाहती हूं कि 1969 में रोजगार में महिलाओं का परिमाण 11 परसेंट था वह 1979 में 12.4 परसेंट हुआ। जहां केन्द्र का इतना बजट होता है, हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम राज्यों को भी बार-बार कहते हैं कि राष्ट्र की योजनाओं में महिलाओं का बल बढ़े, वहां दस साल में रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत केवल 1.3 बढ़ा है। रोजगार में महिलाओं की इतनी बढ़ोतरी हुई है। मैं मंत्री महोदय आप से पूछना चाहती हूं कि हम दहेज के खिलाफ कानून, बलात्कार के खिलाफ संरक्षण देने के लिए, समाज में उनका दर्जा ऊपर उठाने के लिए कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं लेकिन समाज में जिस चीज से उसका दर्जा ऊपर उठ सकता है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? जब तक महिला आर्थिक रूप से दुर्बल रहेगी, उसको सर्विस नहीं मिलेगी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका समाज में स्थान ऊपर नहीं उठ सकता है। वह घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसका पति भी और समाज भी अगर उसके खिलाफ अन्याय करता है तो वह आवाज नहीं उठा सकती। इसलिए महिलाओं को विशेष संरक्षण देने के लिए, महिलाओं का आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए महिलाओं का रोजगार में प्रतिशत बढ़ाना बहुत जरूरी है।

आपने इस नोट में जो दिया है उसको पढ़ कर बहुत दुःख हुआ। आपने यह कहा है कि

आज तक गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाये। महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका ब्यौरा आपने इस नोट में दिया है। यह जो आपका कागज पर लिखा है, वह हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि उन कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन क्या है? हम बीस सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं, हम उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं, उनमें खेतों में काम करने वाली चाहे महिलाएं हों, चाहे और कहीं काम करने वाली महिलाएं हों, उनका सहयोग कहां तक आप लेना चाहते हैं। खास तौर पर हम इस हाउस में यह नहीं सुनना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम हैं, कानून में उनके बारे में क्या हैं। आपने महिलाओं में पिछड़ेपन को खुद माना है। जो हमारे रोजगार कार्यालय हैं, जिनके द्वारा भूले-भटके, शिक्षित और अशिक्षित बेकारों को काम मिलता है, उनमें भी 7 प्रतिशत महिलाओं का है, और 8 प्रतिशत पुरुषों का है।

हमारे कार्यालय काम नहीं करते हैं। सारे क्षेत्रों में उस कार्यालय का अधिकार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, अर्द्ध सरकारी संस्थाएं और कोआपरेटिव संस्थाओं में जो लोग रखे जाते हैं वे इस कार्यालय द्वारा नहीं रखे जाते। इन क्षेत्रों को भी इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तभी देहाती क्षेत्रों के गरीब और मजबूर लोगों को काम मिल सकेगा।

आपने बताया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण में महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। मैं बताना चाहती हूं कि सारे देश में इंजीनियरिंग कालेजेज की संख्या 1084 है जिसमें से महिलाओं के लिए केवल 125 हैं। और संस्थाओं में भी एडमीशन में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे देश की महिलाएं स्कूल टीचर ही बन सकती हैं। 100 रुपया महीना देकर उनसे बालवाड़ी केन्द्र जहां पर बच्चों की देखभाल होती है वहीं चलवाया जाता रहेगा। क्या हमारे देश की महिलाएं केवल अस्पतालों में नर्सें बनने के ही काबिल हैं। मैं जानना चाहती हूं कि टेक्निकल एजूकेशन महिलाओं को देने के लिए क्या सोचा जा रहा है जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारी महिलाएं आगे आ सकें।

जब हम काम करने वाली महिलाओं के बारे में विचार करते हैं तो हमारे सामने आफिस में काम करने वाली महिलाएं डाक्टर, नर्सें आती हैं। कृषि में काम करने वाली महिलाएं हमारे सामने क्यों नहीं आती जो देश की भूख मिटाने के लिए कृषि कार्य में लगी हुई हैं। क्या उनको कृषि से संबंधित नया तकनीकी ज्ञान देने के बारे में कभी सोचा गया है। उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है।

आपने कह दिया है कि यह कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। लेकिन जिस तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा लिया जाता है उसी तरह से इस बारे में भी राज्यों से जानकारी मंगाई जाती है या नहीं। महिलाओं को रोजगार देने के बारे में, उन्हें व्यावसायिक सुरक्षा और पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के इंप्लीमेंटेशन के बारे में हर महीने नहीं तो कम से कम एक साल में ब्यौरा मंगवाया जाना चाहिए यह देखा जाना चाहिए कि किस किस राज्य में कितनी प्रगतिइस बारे में हुई है। इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है

अन्त में एक बात में कहना चाहती हूं। अधिकांश राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में सलाहकार समितियां हैं। केन्द्रीय स्तर पर भी सलाहकार समिति है। मैं पूछना चाहती हूं कि इतने साल तक ये समितियां काम कर रही हैं तो इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। महिलाओं को संरक्षण और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व देने के लिए समिति ने कौन से सुझाव दिए हैं और आपने उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है। यह मैं जानना चाहती हूं।

अन्त में मैं जिस क्षेत्र में आती हूं उस महाराष्ट्र क्षेत्र और उससे लगे हुए गुजरात क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। वहां के टेक्सटाइल उद्योग के बारे में मेरी बहन बताएंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि किसी समय में हमारे यहां हैंडलूम मशहूर थी। नागपुर और शोलापुर आदि शहरों में घर-घर में महिलाएं इस कार्य में लगी हुई थीं। विधवाएं और परित्यक्ता महिलाएं इस काम में लगी थीं जो इससे रोजीरोटी कमाती थीं और अपना पेट पालती थीं। इसके बाद टेक्सटाइल उद्योग खड़ा हो गया। उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या हम महिलाओं को अधिक सहूलियतें देने जा रहे हैं या औद्योगिक विकास के साथ उनका हक कम करने जा रहे हैं?

नागपुर में एक एम्प्रेस मिल है जहां दस साल पहले पचास प्रतिशत महिलाएं काम करती थीं। लेकिन आज उनकी संख्या घटकर केवल दस प्रतिशत रह गई है। आपको यह भी बता देना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए नौकरी की कमी है और उन्हें पगार भी अच्छी नहीं मिलती है। मेडिकल व सुरक्षा की भी सुविधाए महिलाओं के लिए नहीं है। बीड़ी उद्योग और चाय-बागान जैसी जगहों पर भी महिलाओं को कम वेजेज पर काम करना पड़ता है। उनके लिये सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। बीड़ी उद्योग में तम्बाकू के साथ काम करते हुए महिलाओं को सबसे ज्यादा टी० बी० हो जाती है। आप अगर पता लगायेंगे तो मालूम पड़ जायेगा कि सबसे ज्यादा परसन्टेज टी० बी० से पीड़ित महिलाओं की हैं। महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं गिरी हुई हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि वे सच्ची सेवा करती हैं, रिस्क उठाती हैं फिर भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जहां व्यवस्था है वहां हम उनको समावेश नहीं कर पाते हैं। आखिर मैं यही कहना चाहती हूं कि सिर्फ रोजगार देना, प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं बढ़ाना ही काफी नहीं है, उनका समाज में प्रोटेक्शन भी बहुत आवश्यक है। स्कूल, कॉलेज या जो खदाने हैं, उनके पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं। ऐसी जगहों पर महिलाओं के लिए आना-जाना काफी मुश्किल हो जाता है। हम सरकार से इम्पलीमेंटेशन चाहते हैं। कागज पर हमारे लिए क्या व्यवस्था है, इस पर हम विश्वास नहीं करते। इसी के मैं, साथ आपसे जवाब सुनने की अपेक्षा करती हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने बेरोजगारी के बारे में जो भी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं सहमत हूं। हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी है और बढ़ रही है। कुछ दिन पहले बेरोजगारी पर ही एक रेजोल्यूशन इसी हाउस में आया था और तफसील के साथ चर्चा भी हुई थी। मेरे कलीग श्री धर्मवीर जी ने उसका जबाव भी दिया था। यह जो बेरोजगारी की समस्या है सिर्फ महिलाओं की ही नहीं है। यह समस्या पुरुषों की भी है। हमारे सामने यह सवाल चल रहा है कि क्या महिलाओं की मजदूरी या बेरोजगारी बढ़ रही है या महिलाओं को जो एम्पलायमेंट मिलता था, वह घटा है। मेरे पास आंकड़े हैं। आंकड़ों के द्वारा ही मैं आपको सही स्थिति बता सकूंगा। जितने भी आंकड़े हमने जमा किए हैं, वे सब एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिए से ही किए हैं। हमारे देश में एम्पलायमेंट में महिलाओं का शेयर 1975 में 11.3 था। 1976 में बढ़कर 11.8 हो गया, 1977 में 11.9 हो गया, 1978 में 12 हो गया, 1979 में 11.9 रहा, 1980 में बढ़कर 12.1 हो गया और 1981 में बढ़कर 12.2 हो गया। तो जो महिलाओं का शेयर है वह बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं मानता हूं कि जो बढ़ रहा है उसकी गति धीमी है क्योंकि 1975 में 11.3 से बढकर 1981 में 12.2 तक ही आया है। लेकिन जो प्रश्न माननीय सदस्या ने मुझ से पूछा था कि क्या महिलाओं के लिए रोजगारी की जो फैसिलिटीज या अपोर्चुनिटीज हैं वह कम

हो रही है ? तो आँकड़े सिद्ध करते हैं कि कम नहीं हुई हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन धीमी गति से बढ़ रही हैं। और एक प्रश्न माननीय सदस्या ने यह भी पूछा कि देश के अन्दर कुल 1084 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस हैं उनमें सिर्फ 125 महिलाओं के लिए हैं। तो माननीया सदस्या को यह कनफ्यूजन हुआ कि केवल 125 महिलाओं के लिए हैं और वकिया पुरुषों के लिए हैं। यह बात नहीं है। बल्कि जो दूसरे हैं वहां दोनों जा सकते हैं। और जो 125 हैं यहां सिर्फ महिलायें ही जा सकती हैं, पुरुषों का एडमीशन नहीं है।

इसी के साथ साथ मैंने यह भी बताया था कि नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1977 में कायम किया है यह भी महिलाओं के लिए है इसके अलाबा एक रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बम्बई में कायम हुआ है। और इसके साथ-साथ हमारे सामने और भी प्रोपोजलस हैं। और 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग सेट अप करना चाहते हैं। लेकिन अभी नहीं कर पाए हैं, जल्दी से जल्दी उनको सेट अप करना चाहते हैं।

मैंने बताया कि जो बेरोजगारी का सवाल है वह दोनों के लिए मसावी है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में बताया था कि ऐमप्लायमेंट ऐक्सचेंजज के जरिए से जितने लोग भी रोजगारी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं महिलाओं में तकरीबन 7 परसेंट को रोजगार मिलता है और पुरुषों में 8 परसेंट को रोजगार मिलता है। यह नहीं है कि महिलाओं को ऐमप्लायमेंट बहुत कम मिलता है और पुरुषों को बहुत मिलता है। पुरुषों और महिलाओं की हालत तकरीबन समान है, केवल 1 परसेंट का डिफरेंस है। तो यह हालत इसलिए है कि हमारे देश में बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी क्यों है ? इसको कैसे दूर करना चाहते हैं ? उसके लिये तो बहुत सी स्कीम्स हैं, प्लान में भी...

MR. DEPUTY SPEAKAR : The populations ofmen and women are equal. Therefore, are should not be more than the other. That you agree.

SHRI VEERENDRA PATIL : I am coming to that also.

SHRI T.C. DHANDAPANI : The population of women is more.

SHRI VEERENDRA PATIL : और मैं यह मानता हूं कि जितने पुरुष काम करते हैं उतनी महिलायें काम नहीं करती हैं। वह तो है ही। मैंने कहा महिलाओं का शेयर 12 परसेंट है। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह लिमिटेशन्स यह हैं कि कुछ ऐमप्लायमेंट ऐसे हैं जहां पर महिलायें रात में काम नहीं कर सकती हैं।

आई० एल० ओ० का कन्वैशन हमने मान लिया है, रैटीफाई किया है। उस कनवैंशन के लिहाज से, मैं मिसाल देना चाहता हूं कि फैक्टरी एक्ट, माइन्स एक्ट, प्लान्टेशन एक्ट, बीड़ी-सिगरेट ऐक्ट के मुताबिक हमने इनमें महिलाओं को काम करने से प्राहीबीट किया है। रात में वह काम नहीं कर सकती हैं।

इसके अलावा एक फैक्टर और है जो हमें और आपको सोचना है। महिलायें अगर काम करना चाहती हैं तो कभी-कभी एम्पलायर यह सोचता है कि अगर महिलाओं को एम्पलाय करेंगे तो वह कास्टली हो जायेगा बनिस्बत पुरुष के क्योंकि हमारे यहां लेबर लाज के लिहाज से कुछ सहूलियतें, कुछ एमिनिटीज उनको देनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर मैटरनिटी बैनिफिट उनको देना पड़ता है। डिलीवरी के 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद का पूरा वेतन, मजदूरी उनको देनी पड़ती है और यह फैसिलिटी भी देनी पड़ती है। कभी-कभी एम्पलायर यह सोचता है कि अगर महिला को एम्पलाय करेंगे तो कास्टली हो जायेगा तो वह उसको डिस्करेज करता है। लेकिन मैं यह भी

बतलाना चाहता हूं कि यह हालत पहले थी, अब हालत बदल रही है और सुधर रही है।

बहुत से ऐसे एम्पलायमेंट हैं जहां लेडीज को प्रैफरेन्स दिया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी आफिस में जाइये तो रिसेप्शनिस्ट लेडी होगी, होटल में रिसेप्शनिस्ट लेडी होंगी। एयर होस्टैस की जगह महिलाएं काम करती हैं। और भी कई प्रकार की नौकरियां हैं जहां महिलाएं काम करती हैं। इसी प्रकार बहुत से सदस्यों को मालूम है कि खेती में भी महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनके फिगर्स हमारे पास नहीं हैं। बीड़ी इंडस्ट्री में काम करती हैं, फिश प्रासेसिंग, फूड प्रासेसिंग एंड फूड प्लानिंग में स्त्रियां काम करती हैं। इसी प्रकार टेलीफोन फैक्टरीज हैं, काटेज इंडस्ट्री हैं जहां सबसे पहले लेडीज को प्रैफरेन्स मिलता है। लेडीज को एम्पलायर खुद प्रैफरेन्स देता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : 50 परसेन्ट जनसंख्या के लिये क्या यह दो तीन कम्पनी काफी हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टरीज में बहुत कम लेडीज काम करती हैं। हम नहीं चाहते कि वह फैक्टरीज में काम करें।

Mr. Deputy Speuker : Let him conclude. You like one theme that the managers of the homes are all ladies.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मंत्री महोदय महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह कह रहा हूं कि कानूनन महिलाएं वहां पर काम नहीं कर सकती हैं। जो हैजार्डस काम होता है, वहां पर महिलाओं को काम करने का मौका नहीं दिया जाता। अंडर-ग्राउन्ड माइन्स में महिलाओं को काम करने की इजाजत कानून से नहीं है। जहां कानून के मुताबिक महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, वहां के बारे में यह बोलने का कोई फायदा नहीं है कि हम वहां उनको काम का मौका देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं को आज ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिये और उनके लिये एम्पलायमेंट की अपार्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिये। इसके लिए एडवाइजरी कमेटी स्टेट लैवल पर भी होनी चाहिएं और उसी तरह से बहुत सी स्टेट्स में हमने कहा है कि वीमैन सैल भी बननी चाहिएं ताकि किस तरीके से उनके लिए एम्पलायमेंट के एवेन्युज और अपार्चूनिटीज निकल सकते हैं, यह देखे जाएं।

"A Steering Group on Women for employment to quantify domestic work relating to families rendered by women and to suggest ways and means to divert some of this work to better productive work."

"Based on the suggestion of the Group, the National Council of Applied and Economic Research would be conducting an indepth sample survey of 2,000 households in four States on women's work and employment from April, 1983."

प्लानिंग कमीशन ने एक स्टियरिंगग्रुप कायम किया है, जो इस बारे में स्टडी कर के गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देगा।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : क्या उस ग्रुप में महिलाएं है या मर्द हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इतना ही मालूम है कि प्लानिंग कमीशन ने औरतों को ज्यादा एम्पलायमेंट आपर्चुनिटीज मुहैया करने के लिए यह स्टियरिंग ग्रुप कांस्टीच्यूट किया है। मेरे पास ये तफसीलात नहीं हैं कि उस ग्रुप में मेम्बर कौन-कौन हैं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में महिलाओं के लिए कितनी टेकनिकल इंस्टीट्यूशन्ज हैं ?

महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के लिए तकनीकी विद्यालय खोलने की मांग बरसों से की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई टेकनिकल स्कूल या पालिटेकनिक नहीं खोल सकी है। इससे राज्य सरकारों की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति का पता चलता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक देहात में महिलाओं के लिए टेकनिकल एजूकेशन की सुविधाओं का सवाल है, मेरा ख्याल है कि हर स्टेट में कई आई टी आई, पालिटेकनीक और टेकनिकल स्कूल हैं। मुझे मालूम नहीं है कि क्या हर देहात में ऐसी इंस्टीट्यूशन्ज हैं। हर देहात में वे नहीं हो सकतीं। लेकिन बड़े बड़े देहात में वे होंगी। कहाँ पर आई टी आई होना चाहिए, कहां पर पालिटेकनीक होना चाहिये और कहां पर टेकनिकल स्कूल होना चाहिये, उसकी फिक्र और उसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट का गामला है। वे अपनी पालिसी और प्रोग्राम के मुताबिक एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज चलाते हैं। मैं मानता हूं कि आज-कल की बी ए और एम ए की पढ़ाई के बजाए टेकनिकल एजूकेशन की ज्यादा फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है।

माननीय सदस्या ने कहा है कि टैक्स्टाइल इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या कम हो रही है। मेरे पास उसके फिगर्ज हैं। पूरे देश में मैनुफेक्चर आफ काटन टैक्स्टाइल में 1976 में 84,300 महिलाएं काम करती थीं, जबकि 1980 में-1981-82 के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। 88,100 महिलाएं काम करती थीं। उनकी संख्या में 4000 की वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई। इसी तरह मैनुफेक्चर आफ टैक्स्टाइल प्रोडक्ट्स इनक्लूडिंग वियरिंग ऐपेरेल अदर दैन फुटवियर में 1976 में 20,600 महिलाएं काम करती थीं, जब कि 1980 मे 25,500 महिलाएं काम करती थीं। वहाँ भी महिलाओं की तादाद घटी नहीं है, बढ़ी है। लेकिन वह तादाद बहुत बढ़ी है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बिल्कुल समाधान नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ रंग-रंगोटी कर के जवाब दिया है। मैं सदन के सामने वास्तविक स्थिति रखना चाहती हूं। इस बारे में सदन में पहले दो बार बात हो चुकी है आपको विदित होगा कि यहां पर यह आवाज उठाई गई थी कि केरल में तम्बाकू इंडस्ट्री में नई मशीनरी लगाने की वजह से 50,000 बहनों को काम से निकाला जाएगा। पब्लिक सैक्टर की कम्पनी बी० सी० सी० एल० में महिलाओं की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। 1972 में वहां 30,000 महिलाएं काम करती थीं।

हर साल कितनी कम हुई हैं वह मैं आपको बता सकती हूं।

एक न्यूज आइटम इंडियन एक्सप्रेस में निकला था जिसके हिसाब से 1973 में 30 हजार बहनें लगी हुई थीं जोकि 1977 में 19,754 रह गई, 1978 में 18,084 रह गई, 1979 में 16,764 रह गई और 1982 में वह घटकर 12,000 ही रह गई। वहां पर एक सर्कुलर भी निकाला गया था जिसको मैं आपको पढ़कर भी सुना सकती हूं, जिसमें मैनेजमेंट ने लिखा है सभी बहनों को कि आपके बदले में वे किसी लड़के को लेना चाहते हैं, उसको काम पर लगाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा है कि किसी जवान लड़की को भी वे काम पर लेना चाहते हैं। लिखा है कि सिर्फ लड़के को काम पर रखना है आपके बदले। इसका मतलब यह है कि धीरे-धीरे वालन्टरी रिटायरमेंट दिलाकर महिलाओं को काम से निकाला जा रहा है।

बाम्बे में बहुत बड़ी टेक्स्टाइल इण्डस्ट्री है और वहां पर स्ट्राइक भी चल रही है। जहां 20 परसेन्ट महिलायें काम कर रही थीं वहां

पर अब केवल 9 परसेन्ट ही रह गई हैं और उसमें भी 90 परसेन्ट महिलाएं जो हैं, वह 40 साल से ऊपर की हैं। इसका मतलब यही है कि वे धीरे-धीरे रिटायर हो जाएंगी और फिर बहनों को वहां पर काम में नहीं रखा जाएगा।

यह तो मैं आपको आर्गेनाइज्ड सेक्टर की हालत बता रही थी। यही हालत खेती में भी है। जो टेक्नोलोजीकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका असर बहनों पर पड़ रहा है। 96 परसेंट बहनें अनार्गेनाइज्ड सेक्टर में ही लगी है और उसमें से भी अधिक से अधिक एग्रीकल्चर में हैं। 9 मार्च को हमने इन्टरनेशनल वीमेन डे मनाया था और एक जुलूस भी निकाला था और वीमेन एम्पलायमेंट के लिए एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिया था। उसमें हमने लिखा था कि आज बहनों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहा, दूसरी प्रकार की एट्रासिटीज हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है और फिमेल इन्फैन्टिसाइड के साथ साथ फ्वाटिसाइड भी किया जा रहा है। इस तरह से उनका जीना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको काम से निकाला जा रहा है 1971 की सेन्सस में भी महिलाओं के काम का आर्थिक मूल्य नहीं लगाया गया। जो औरतें अपने पति के साथ खेत में काम करती हैं या अगर कोई आदमी पकौड़े बेचता है और उसकी पत्नी पकौड़े बनाकर देती है तो भी उसको बेकार बता दिया गया। कब दिया गया कि वह कोई आर्थिक काम नहीं हैं। जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो 1977 के बाद प्लानिंग कमीशन ने इन कामों के आर्थिक मूल्य को माना। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐअर होस्टेसेज के बारे में जजमेन्ट दिया कि रिटायरमेन्ट में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में कितने एयरहोस्टेसिस के एप्वाइंटमेन्ट हुए ? मैं देखती हूं कि आजकल हवाई जहाज में एयर-होस्टेसिस का एप्वाइंटमेन्ट नहीं होता है। मेरे पास शिकायतें हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारी प्रधानमन्त्री ने कहा है—
At the age of 45, our women are not sufficiently alert enough, dutiful enough to be Air Hostesses.

महिलाओं में शिक्षा कम होती है, इसलिए उनको काम से निकाल दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अशिक्षित होने के क्या कारण हैं, इसका आपको पता लगाना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे क्रेच की भी मांग करती हूं। काम की जगह पर नहीं, बल्कि हर स्कूल के पास। यदि आप इसकी व्यवस्था करेंगे तो लड़कियां स्कूलों में पढ़ने के लिये जाएंगी। समस्या यह है कि लड़की के माँ-बाप के मन में यह होता है कि छोटे भाई-बहनों को कहां रखा जाएगा। यदि आप इसकी व्यवस्था कर देंगे, तो बहुत लड़कियां पढ़ने के लिये जाएंगी — ऐसा मेरा अनुभव है। एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर आप इसकी व्यवस्था करके देखिए। लड़कियां बचपन में पढ़ती नहीं है, इसके आगे चल कर जब उनको काम पर जाना पड़ता है तो वे उस काबिल नहीं रहती हैं। इसलिए हमारी मांग है कि क्रेचेज काम की जगह पर ही नहीं बल्कि स्कूलों के पास होने चाहिए गावों में। प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लास तक गांवों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए, इक्युवल रिम्युनरेशन और मैटरनिटी बेनिफिट कानून हैं।
But the employers are not interested in employing women.

इसका असर एम्पलायमेन्ट पर हो रहा है। मालिक लोग समझते हैं कि यदि महिलाओं को काम देंगे तो मंहगाई हो जाएगी। मैं यह समझती हूं कि महिलाओं को जब कम तनख्वाह दी जाती थी तो इंडस्ट्रीज में बहनें ज्यादा थी। मैं यह कहना चाहती हूं कि मातृत्व होना क्या कोई गुनाह है ? मेरी दृष्टि में यह गुनाह नहीं है।

यह रिसपांसिबिलिटी है । मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह एम्पलायमेन्ट इंशोरेन्स स्कीम है, उसी तरफ से बेनिफिट स्कीम फार दी विमेन बनाइए । किसी भी कारखाने में पुरुष को भी काम पर रखें तो उस पर नामिनल सैंस लगाइए, जिसमें स्टेट गवर्नमेन्ट कन्ट्रब्यूट करे । आप इस तरह का एक फंड बना दीजिए, जिसके जरिए देश में कहीं भी महिलाएं काम करेंगी तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी । यदि हम मालिकों पर छोड़ देते हैं, तो वे महिलाओं को काम पर नहीं लेंगे । एक सेमीनार हुआ था, उसमें एक जैन डाक्टर है, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा था । उन्होंने विशाखापटनम और अहमदाबाद के बारे में कहा था ।

25% to 50% women seek employment and most of them are from the poorer classes. राजस्थान में उन्होंने कहा है

67% of the people go out for employment. Out of that 14% are women वे काम पर जाना

चाहती हैं, काम की बहुत जरूरत है । जिनका परिवार गरीब होता है, वही ज्यादा से ज्यादा बहनें काम पर निकलती हैं । आपको पता है एम्पलायमेन्ट गारन्टी स्कीम में चीजें कम मिलती हैं । तनख्वाह कम है । 62% of the women are taking jobs there. बहनें काम करने के लिए तैयार हैं । जैसे स्त्री सुरक्षा की बात करते हैं, वैसे फैमिली वैलफेयर पर भी विचार करना चाहिए । रिसर्च से यह पता चला है कि जहां बहनें काम करती हैं, वहां 100% of their income goes for the welfare of their family. खाना-पीना और बच्चों की शिक्षा के लिए होता है । पुरुष की More than 50% income is spent on vice practices, कभी शराब होती है, कभी मटका होता है और कभी दुसरी चीजें होती हैं । महिलाएं इससे बहुत परेशान और दुःखी होती है ।

Most of the 50% of income is spent on this.

मुझे यह कहना है कि सरकार के दिमाग में जो यह बात है कि

Women's employment is marginal.

यह मार्जिनल ईशू नहीं है, मेजर ईशू है । एक मेजर ईशू कह कर एक चैप्टर लिखने से महिलाओं की एम्पलायमेंट में सुधार नहीं होगा । इसके बारे में आपको सोचना चाहिए —

Women's employment should be given priority. Everywhere, a minimum of 25% of jobs should be reserved for women.

उनको काबिल बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी । आपने आंकड़े दिए हैं—आई०टी०आई० के 125 स्कूल बने हैं । हमें आपसे यह जानना है कि आप ने जो आंकड़े दिए हैं—1084 इंस्टीट्यूशन्ज इनमें कितनी बहनें हैं ? That you have not told us. You have just said 125, only for women.

125 में भी कितनी बहनें जाती हैं ? मुझे दुःख यह है कि because women are not sufficienty literate, even more seats in these institutions should be vacant.

क्योंकि हमारे यहां महिलाओं की शिक्षा ज्यादा नहीं है । हमारे देश में कितनी बहनें कालिजिज में जाती हैं, कितनी बहनें 10वीं पास करती हैं, कितनी बहनें चौथी तक पढ़ती हैं ? हमारी शिक्षा का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अनपढ़ भी हो तो टैक्नीकल एजूकेशन देकर उसको काम पर लगाया जा सके ।

हमारी बहुत पहले से यह मांग रही है—— 1975 में स्टेटस आफ वुमेन कमेटी ने यह रिकमेण्डेशन की थी, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं की एजूकेशन का प्रश्न, महिलाओं की हैल्थ का प्रश्न— These are all related issues, inter-dependent. उन्होंने मांग की थी और मैंने भी यहां जिक्र किया है——We must have a National Commission on Women, with statutory powers.

उसकी रिपोर्ट हमेशा पार्लियामेन्ट के सामने आनी चाहिये। हम बहुत बार सवाल पूछते हैं-- हमको उस का उत्तर नहीं मिलता है, यदि मिलता भी है तो उसके बारे में शक होता है। 1978 में एक नेशनल कमेटी आन वुमेन बनी थी, मैं उसकी सदस्य थी। उसका चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। जब जनता पार्टी का राज था, तब मैं दिल्ली में थी और उसकी तीन-चार मीटिंग्ज में शामिल हुई। लेकिन 1980 से आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। इस वक्त एक वुमेन उसकी चेयरमेन है—She happens to be the Prime Minister of this country; but still not a single meeting has taken place.

वह उस नेशनल कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाती हैं। इसलिए मैं कहती हूं—जब तक पोलिटीकल विल नहीं होगा, यह काम नहीं होगा। हम महिलाएं अब धीरे-धीरे इकट्ठी हो रही हैं— We are convincing women: 'You are the voters. It is a very important thing.' माइनारिटी कमीशन है, इसलिए कि माइनारिटीज का वोट चाहिये। शैडयूल्ड कास्टस और ट्राइब्स कमीशन है क्योंकि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का वोट चाहिये, लेकिन महिलाओं के वोट के लिये नेशनल कमीशन आन वुमेन बनाने के लिये सरकार तैयार नहीं है। अब समय आने वाला है जब हमारी सब बहनें, जो पार्टी उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम नहीं करेंगी, हम उनको वोट नहीं देंगे।

MR. DEPUTY SPEAKER: In every constituency, you can put up one lady candidate.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : यह हमें अब करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछती हूं—इसके बारे में आपकी कमिटमेंट है या नहीं? This is not the recommenation only of the Status of Women Committee.

इन्होंने भी रिकमेंड किया है और इन्टरनेशनल वुमेन डिकेड में कहा है, आइ०एल०ओ० ने भी रिकमेण्ड किया है—इसलिये मैं आपसे पूछती हूं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? नेशनल कमीशन आन वुमेन बनाया जाय और उसकी मीटिंग करके उसमें सभी समस्याओं के बारे में विचार कर सकते हैं।

अब मैं संक्षेप में तीन-चार सवाल पूछना चाहती हूं —

1. जहां पर बहनों का रिट्रेन्चमेंट होता है, बहनों को निकाला जाता है और फिर री-एम्पलायमेंट होता है—Are you going to give us a guarantee that wherever women are retrenched. वापस लेते समय केवल बहनों को नहीं लेंगे।

2. मैंने बी०सी०सी०एल० का सवाल रखा है और उस सरकुलर को विड्रा करने के लिए कहा है। वहां बहनों को निकाला जा रहा है, यह ठीक नहीं है।। Most of the women are from tribal and Harijan families.

टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज में आप बतलाते हैं— बम्बई में ऐसी बात नहीं है—

I can only judge the textile industry, from Bombay. इसलिये प्रार्थना है कि आप बतलायें— कितनी बहनों की रखेंगे। बहनों की एम्पलायमेंट के लिए जो लीगल प्रोटेक्शन है, यदि वह उनके खिलाफ जाता है तो मैंने जो सुझाव रखा है कि कामन फण्ड होना चाहिए, महिलाओं की सारी दिक्कतें दूर करने के लिए सरकार की ओर से आप जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे? क्या आप यह विश्वास दिलायेंगे कि आप उनकी सभी दिक्कतों को दूर करेंगे। नेशनल कमीशन आफ वीमेंस के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्या ने कुछ सुझाव रखें हैं। पहला सवाल तो उनका यह है कि केरल में एक जी० सी०एल० फैक्टरी है जिसमें कि, जहां तक मेरी जानकारी है तम्बाकू बलेण्ड करने के लिए मशीन लगाना

चाहते हैं और उससे माननीय सदस्या को डर है कि महिलाओं का रिट्रेंचमेंट हो सकता है। मेनेजमेंट वालों का यह कहना है कि अगर मशीन से तम्बाकू बलेण्ड होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और उसके लिए एक्सपोर्ट मार्किट भी बहुत अच्छी रहेगी, वे ज्याद एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादा फोरन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, उसके चेअर-मेन ने हमें विश्वास दिलाया है कि यह मशीन लगने के बाद जो महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, जिनकी रोजगारी कम होगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको रिट्रेंच नहीं किया जाएगा। लेकिन माननीय सदस्या का जो यह कहना है कि मशीन लगने के बाद हजारों की तादाद में महिलाएं बेरोजगार हुई हैं, मुझे वह मालूम नहीं है और न उसकी जानकारी मेरे पास है। मैं मालूम कर सकता हूं।

अब सवाल यह है कि हमारे जो मेन्युफेक्चर्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उनकी प्राइसिज भी कम्पीटिटिव होनी चाहिए। अगर क्यालिटी अच्छी नहीं है, प्राइसिज कम्पी-टिटिव नहीं हैं तो वह इंडस्ट्री सफर करेगी और बन्द भी हो जाएगी। इसलिए कभी कभी फेक्ट्री का माडरेनाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हम हमेशा यह कहते आ रहे हैं और मैनेज-मेंट पर दबाव भी डाल रहे हैं कि जब कभी माडरेनाइजेशन होता है और उसकी वजह से कोई रिट्रेंचमेंट होता है तो आल्टरनेटिव जोब ढूंढ़ने की जिम्मेदारी मेनेजमेंट के ऊपर है।

हमने बताया है कि कुछ इंडस्ट्रीज में महिला मजदूर ज्यादा काम कर रही हैं। मेरे पास इंडस्ट्रीवाइज फिगर्स नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास मेजर इंडस्ट्रीज के फिगर्स हैं। हरेक इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट केर फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। यह हो सकता है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में महिला मजदूर कम हुई होंगी, कुछ में ज्यादा हुई होंगी। मेरे पास जो आल इण्डिया पिक्चर है उसके लिहाज से मैं कह सकता हूं कि महिलाओं में एम्पलायमेंट अपारच्युनिटीज कम नहीं हुई हैं, वे ज्यादा हुई हैं। यह मैं मानता हूं कि वे बहुत ज्यादा भी नहीं हुई हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्या का यह कहना कि गवर्नमेंट को एम्पलायर को मजबूर करना चाहिए कि अगर कोई भी वहां पर वेकेन्सीज हों तो उन पर महिलाओं को प्रायोरिटीज देनी चाहिएं।

अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है कि इस तरह के कोई डायरेक्टिव्स...।

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : My point is that wherever there is retrench-ment of a woman and when it comes to filling up that post, that post should be filled by a woman only.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्या का यह कहना कि किसी फैक्ट्री में जब कभी भी महिलाओं का रीट्रेंचमेंट हो तो वह जगह महिलाओं से ही भरनी चाहिए और अगर पुरुषों का रीट्रेंचमेंट हो तो पुरुषों से भरनी चाहिए।

SHRI CHITTA BASU :**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let them get a reply from the Minister. This is not a general discussion. Why are you interrupting ? Please do not record this interruption.

(*Interruptions*) **

MR. DEPUTY-SPEAKER : Calling Attention is going on. Why have you come in the middle ? Sometimes, we lose concentra-tion in the House because of so much of interruption. You take everything so lightly that the concentration is spoiled. I request the House to give attention.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अगर माननीय सदस्य शांति से सुनते हैं तो मैं कुछ बोल सकूंगा। डिस्टरबेंस होगा तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक इस विषय का संबंध है यह कोई विवादास्पद विषय नहीं है। इससे हम भी सहमत हैं और आप भी सहमत हैं। सवाल यह है कि इसको किस तरह से निपटाना है। इसके लिए इस तरफ के लोगों को भी सोचना है और

**Not recorded.

उस तरफ के लोगों को भी सोचना है। यह जो सुझाव माननीय सदस्या ने दिया है कि जब महिला मजदूरों का रीट्रेंचमेंट होता है तो उनकी जगह महिलाओं को रखा जाना चाहिए। इस तरह का क्या हम आर्डर कर सकते हैं, इसके लिए में एग्जामिन कराऊंगा। मैं इस बात को एकदम से टालना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंश हैं और कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन भी है, उसके हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते। 25 फीसदी या इस तरह का कोई भी प्रतिशत महिलाओं के यदि हम रखना चाहें तो कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन आर्टीकल 16 (2), 16 (3) और 16 (4) के अन्तर्गत हम ऐसा रिजर्वेशन नहीं कर सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में 3 परसेंट रिजर्वेशन किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is making out a point. He is replying. Please do not record any interruption other than Pramilaji and the Minister. This is not a general discussion.

This is not a general discussion. He is replying to Mrs. Pramila Dandavate. Whatever you interrupt it is not doing on record also. Any interruption during Calling Attention is not going on record. Only Pramila Ji's question and Minister's reply will go on record.

Shri Veerendra Patil : कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बता रहा हूं।

Article 16 (1) of the Constitution prohibits discrimination in matters relating to any employment or appointment to any office under the State.

Article 16 (2) provides that :

"No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State".

अगर 25 फीसदी रिजर्वेशन किया जाए तो,

It amounts to discrimination against men.

MR. DEPUTY SPEAKER : Supposing all ladies are elected to Parliament with more than two-third majority, can they not bring an amendment ?

SHRI VEERENDRA PATIL : They can do that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Pramila Ji, you try that, you have to bring an amendment.

SHRI VEERENDRA PATIL : Why only women M.Ps. ? Even now if the entire House agrees that this should be changed, you can amend the Constitution.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : (Panskura) : I will read out Article 15(3). Article 15 (1) says :

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

There is 15 (2) in between, i.e. access to shops, public restaurants, places of public resorts, etc. Article 15 (3) says :

"Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children".

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister will reply. Mrs. Geeta Mukherjee's name is here.

SHRI VEERENDRA PATIL : Sir, the position is that if the Government wants to have any reservation for women under the Constitution, then the entire women as a class should be declared as a backward class. Unless the entire women as a class are declared as a backward class, I do not think reservation is possible.

MR. DEPUTY SPEAKER : We will have a general discussion afterwards. If you want you all give separate notices.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीया सदस्या को और सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करने का प्रयत्न न करें कि रूलिंग पार्टी की महिलाओं के साथ कोई सहानुभूति या सिमपैथी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। महिलाएं उधर भी हैं और इधर भी हैं।

लेकिन सवाल यह है कि इस प्रश्न को किस ढंग से हमें हल करना चाहिये। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में भी बहुत स्कीम्स हैं। मुझे मालूम है कि 1982-83 में उन्होंने महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोगाम शुरू किया है जिस पर 47 लाख रु० खर्च हुआ है। 1983-84 में उनके पास एक करोड़ रु० खर्च करने का प्रोगाम है। इसी तरह से वर्किंग वीमेन्स होस्टल भी बना रहे हैं जगह-जगह। इसलिये वीमेन्स के लिए जो भी सुविधायें पहुंचानी हैं वह सिर्फ लेबर मिनिस्ट्री ही नहीं है, और भी मिनिस्ट्रीज हैं और हर एक के पास उनकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, और कोशिश यह हो रही है कि जितना हो सकता है महिलाओं के लिए एम्पलायमेंट अपोर्चुनिटीज को और बढ़ायें।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Sir, I strongly feel that this is a subject which should have come up for a general diccussion in the House both for men and women, because of the prevalent feeling on the subject.

MR DEPUTY SPEAKER : Give a separate notice. Speaker would be very willing to consider it.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I hope this will be teken up. The main object of this calling attention is to attract the attention of the whole House and, through the House, the whole society to this question.

The Minister was saying thet an impression may not be created that the ruling party was not doing anything, as far as women are concermed. If we have raised this discussion today, focusping attention on this topic, it is not to denigrate the ruling party as such but at the same time, those who rule have a special responsibility, that cannot be denied. Therefore, in order to understand the situation the performance of the government in various fields needs to be taken into consideration.

I am very sorry to say that when I read the strtement first, which was long back, my reaction was that this statement is a projection of smug complacency, cynical insensitiveness and abysmal ignorance, if not deliberate deception. I am sorry to say that in the course of the answer also I have not been able to persuade myself to forget this initial reaction.

Since various figures have been quoted, I shall also give some figures. But, before doing that, I want to draw the attention of the Education Minister to the fact, so far as the data of employmnt of women is cancerned, the question is not whether the percentage has gone up or not, it is a question of whether the relative position of employment of women has gone up, because they constitute 50 per cent of the population. So, the most important question is their relative position.

Before I come to the question of data colletction, though he may be aware of it, I would like to refresh his memory by quoting from page 426 of the Sixth Five Year Plan document, para 7.32, where the Commission says :

> "One of the most important means of achieving improvement in the status of women will be to secure for them a fair share of employment opportunities."

MR DEPUTY-SPEAKER : Because they belong to the fair sex!

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : It says further :

> "The areas where women's employment is either low or on the decline could be identified and correct measures initiated to promote additional avenues for employment."

Sir, if there was no sphere at all where the employment of women was low or on the decline, are we to think that the planning commission was smoking opium when they came up with this particular para ? Bacause, Sir, behind this was a long discussion, many many investgations and several census reports. So, one has to go into that question in order to uuderstand the significance of the whole problem without belittling or lightening the situaton. But before that, as I said, I would like to deal with the question of data collection. You will be surprised to know—here many things have been said, many data have been quoted, I will also quote that, but before that, I would like to say that on the 2nd November I gave an Unstarred Ouestion No. 3487 ragarding women's employment in the organised industry, Central and state Government Jobs, Jobs in public undertakings and employment in rural areas and states. The

answer to that Unstarred question was that, informations are being collected and will be laid on the table of the house.'

This is not thelast question. Again, referring to this queston, I even put a question on the 22nd march 1983, Unstarred Question No. 3910 where I asked: "whether the requisite information has since been collected on all or any one of the aspects, and if so, whether a copy of the same will be laid on the table of the house ?" That was last year, and this is in this year. And the answer—can we anticipate such an answer ?—is "No, Sir". Then it said : "Complete information when collected would be laid on the table of the house."

May I question, what is the basis of the Minister's present data ? There is no data collection machinery and, Sir, let me also remind the Minister thet this dats collection is not just like some of our sycophancy. This alone could really reveal to the society the relative position of women in each one of the fields of employment, either industry or agriculture or services or any other, seeing a few nurses here and there, seeing a few clerks in the banks here and there or seeing some women working in the schools and colleges here and there will not reveal the situation. Sir, it is a matter of great shame and great concern that since 1911 census—I am not quoting the census of 1921, 1931, 1951, 1961 and 1971, but I am just only mentioning that in 1911 the share of women in all othear jobs, other than agriculture, that is, excepting peasantry and agricultural labour, dwindled. In 1911 it was 26.1, in 1951 it was already 23.2, in 1961 it was already 20.4. in 1971 it was already 19.9. The 1981 census is yet to come. if it just comes, then alone detailed figures will be available. I am trying my level best to unearth some, I have not been able to get the whole thing, but I have got a little glimpse here and there. But when it comes to···

SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI (Nabadwip) : It will be 21.4.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Yes, it will be 21.4. My good girl and good friend has got it. She is also my 'girl' and 'friend', both. She is my younger sister. I am thankful to her. just now I was trying my level best for it.

Sir, is it not of great concern that in the entire period of Independence the relative wage of woman in the industry was going down and down and if in 10 years from 19. per centand odd to 20. per centn and old it has come up, can you say that the relative position has really substantially changed? And it is this background which led the Planning Commission to get that particular para inserted, where they wanted that the areas be located where women's jobs are low or declining ? That Job has not been done. Let the minister say 'yes', that it has been done.

As far as data collection is concerned, this was discussed many times, there is a history in regard to that as well. the need for sexwise information on all aspects of employment has been continuously stressed over the last eight years. In 1975, the Labour Minisitry itself started the cell on women's employment. One of the objective of this cell was to collect and publish sex-wise data on employment, training, education etc. the National plan of Action, to which my friend Smt. Pramila Dandavate has referred, was drawn up and after that in 1978 there wat a lot of discussion and it was decided that certain other spheres will be looked after by certain other ministries and this particular aspect will be looked after by the Labour ministry. For that Statistical monitoring Centre has laid special emphasis on measurement of changes in women's employment, wages, working conditions and enforcement of labour laws. They said that these laws should be strengthened in the ministry of Labour. That was the position. Then in November, 1979 the Indian Delegation to the ESCAP Regional Preparatory Conference for UN Mid-Decade Conference organised by the ESCAP in New Delhi moved a recommendation that all national pata collection agencies should provide sexcand age break down for any information they gather. That has not been done. My point is, it is not just a slip. This is deliberate. This is a reflection on the state of consciousness that is there in the society and the ruling party's ministers are not above it. This has been proved by my questeons and the answers which have been given.

Let us come to the substantive position about what is happening in this situation? My

hon. friend Smt. Pramila has already given you figures. In our Call Attention two sectors where the women's work is on decline hav been mentioned—Jute and Textiles. The figures about textiles given by the Minister are concocted. Study has been made by Sujata Ghotoskar, Rohini Banaji, Neelum Chaturvedi. This was published in the Economic and Political Weekly of March 5, 1983. There they have said:

> "In 1951 women constituted 25% of the workers of the textile industry. To-day, they constitute just about 5%".

This has not been contradicted by anybody.

As far as jute is concerned, less said, the better. Hon Member Chitta Basu shows very well about the factories position in Barrachpur belt. We have got hardly any woman left. They are handful. They have been constantly thrown out and no woman has been replaced by a woman. This is the situation. The declining trend is beyond redemption. Why have we today raised the question of jute? The same may become the position in so far as other industries are concerned. Yesterday it happened in jute industry, to-morrow it may happen to Textile industry and even new sector of industries.

The Central Government is the biggest employer. We believe that they should be the pace setters. I wont to take up this important thing in regard to women's employment position in the society or what the Central Government in doing. Ministry of Lobour has published statistics in'Employment Review' of 76-77. It is the Government Ministry and not Women's Ministry. There they say—

There, they say, "In the total public sector women's percentage was 9.34. Among them in the Central public sector it was 3.43 per cent". Now, Sir, in answer to my Starred Question No. 594 on the 18th July 1980, the Minister of Finance stated that the number of women employees in the Central Public enterprises was 47,000 out of the total work force of 18.70 lakhs. I am not very good at Mathematics. Even then Sir, I have taken pains to work out the percentages. Sir, it is 2.51 per cent. Now, which is bigger— 3.43 per cent which was in 1976-77 or 2.51 per cent which was in 1980? None of these figures are supplied by me. These are all Government figures.

Now, why are we so very concerned? Not only the traditional industries have already lost a lot of women, but about the new industries, I quote from the *Statesman* which by any chance is not a paper of my political opinion. Even then, the *Statesman* in its editorial dated 20.3.1980 states:

> "Even the much publicised entry of women into such new vocations as assembly line operations in this electronic industry has proved to be short-lived. A recent study showed that their share of work force dwindled by nearly half in the space of three years newly available training courses and that has an edge during selection."

Sir, these three years and the Sixth Plan years. In respect of electronic industry everybody was saying that women are very good and their precision sense is very good. If in this new sector this is the situation, please think over what is the general situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I have two or three things to say.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: I have already announced that I will not ring the bell, but you have taken 15 minutes.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I will try to be brief. I would not have taken long had the Minister replied in a different way. I have been forced to...

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU (Barsat): She is challenging the figure given by him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister reply. You don't worry. He will reply. He is quite capable of replying.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: If this is the relative position about which we are very much worried......... (*Interruptions*). Sir, in this connection I will also give one instance of textile mills. In the National Textile Corporation mills......let the Minister

know and examine——I have found out that in 1980 where the ration of women employed per thousand men was 1.2, in 1981, even there, it has come down to 1.1.

About the training, a lot has been said here. Very good.

MR. DEPUTY SPEAKER : For my information, shall I put you one question ? Labour is a Concurrent subject. What is the attitude of the respective State Governments ?

(*Interruptions*)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I am not going to defend any State Governments.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not asking about it. Labour is a Concurrent subject. The State Government is also an employer. You know that.

(*Interruptions*)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : In the very beginning I have made it clear that it is not my intention or our intention to go in for politicking. We have brought this to draw the attention of the society and the House.

About the situation with regard to women's training, I am raising this because I saw how even in this new sphere women are driven out for want of training. Here, I shall not go into many things for want of time, but I have to say one thing in order to point out the relative position of women even in this sphere.

In the Sixth Plan Document, in point 26, in para 27.5 it is stated :

> "Under Apprenticeship Training Scheme placement of increased number of women trainees would receive special attention."

It says, apprenticeship training will receive special attention. What special attention is being given under the Apprenticeship Act ? In answer to my Question-Unstarred No. 1485 of First March, 1983, the Minister has informed that in 1980, the percentage of women apprentices taken under this Act was 3.45 ; in 1981, the percentage came down to 2.00 and in 1982, the percentage became 2.03. I would like to know what attention is being paid for taking more percentage of women apprentices. In fact, it is going down from 3.45 in 1980 to 2.00 in 1981.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, you can reply now ! Madam, how much time do you require now ?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Two or there minutes. Now, I am putting the questions. I had to do all this because of the atmosphere created by the Minister in his reply as well as in the statement.

Now, Sir, regarding the question that I would like to ask, I will take only one minute. I do not accept the contention of the Minister about the reservation for which we have already quoted the Constitution. But at the moment, I am not going into that because I understand that it requires a lot of discussion. But still we stand by it.

At the moment, I would like to know from the Minister firstly whether he will look into the promise which was earlier made about the data collection machinery and which I have also referred to. I do not repeat all these things. But I would like to know what he will do.

Secondly, I would like to know what is being done or what will be done for putting into effect the particular paragraph of the Sixth Five Year Plan document wherein the area where the women's employment is low or declining would be concretely identified and rectified. What measures will be taken in this regard?

Thirdly, pending reservations-because I will not say that he should reply today--I would request him not to go into that today because this is not a subject which is mixed with this issue. Pending reservations and seeing the situation even in the Government enterprises - I would not say the States' are much better but a little better--will the Government issue mandatory directives to its own undertakings and companies that women will not be replaced by men? And further, will they issue directives that the women should be taken in much larger numbers than what is being taken now?

What would the Government do to increase the modern training facilities for women? Already many of our friends have said about it and I fully share the view with them. I do not repeat that this aspect is considered to be totally insufficient.

Sir, he has not answered Shrimati Pramilaji's question on the status of National Women Commission. We would like to know what would be their attitude about the Commission?

Lastly, what monitoring machinery will be there at various administrative levels to monitor the women's employment problems as they grow up day by day?

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, I come to the last part of the question which the hon. Member has put. She wants to know whether the Government is prepared to issue a clear directive, at least, to all the public sector units and industries to earmark a bigger share for ladies pending the question of reservation. So far as the reservation is concerned, I have already made the position clear that under the Constitution, it is not possible for us to fix any reservation for women or on the sex basis. It will amount to discrimination and it will be unconstitutional. Another point which I want to make out is that on several occasions, the Supreme Court has ruled that the reservation shall not be more than 50 per cent.

I will try to explain the position so far as reservation is concerned. What is the percentage today ?

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: You are mistaken that reservation for women is another category. In all categories, there will be reservation for women.

SHRI VEERENDRA PATIL: Just now, Mrs. Pramila Dandavate demanded that at least 25 per cent of jobs should be reserved for women. I am coming to the question of reservation. On several occasions, the Supreme Court has ruled that reservation quota shall not exceed 50 per cent. Let us see what is the existing position. The existing position is that for Scheduled Castes, 15 per cent reservation is there ; for Scheduled Tribes, it is 7-1/2 per cent ; for Ex-Servicemen, it is 10 per cent ; for educationally qualified Group D, it is 10 per cent and for handicapped, it is 3 per cent. It comes to 45.5 per cent.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: He is trying to mislead the whole thing. We do not say, besides 47 per cent ; we want 25 per cent reservation for women. This is not our argument. Within this 47 per cent, we want 25 per cent reservation for women.

SHRI VEERENDRA PATIL: I do not understand. So far as Scheduled Caste is concerned, 15 per cent reservation is there. This 15 per cent is reserved for both men and women. There is no separate reservation for women and there is no separate reservation for men. So far as overall 45.5 per cent reservation is concerned, it is for both men and women. I am under the impression that they want 25 per cent reservation in addition to 45.5 per cent. If they want 25 per cent reservation within 45.5 per cent, then I say, when they can enjoy hundred per cent reservation, why they want only 25 per cent reservation ? In this, we have not made any discrimination at all. So far as the demand of reservation for women is concerned, they have now clarified that they do not want exclusively 25 per cent reservation for women in addition to this overall reservation for various categories.

So far as this matter is concerned, my immediate reaction is that it is not possible to do it under the existing provisions of the constitution. So far as this matter is concerned, whether it is possible to do it under the existing provision of the Constitution or not, I am prepared to refer this matter to the Law Ministry and get it examined. Supposing the Law Ministry feels that it is possible, then, I think, it is for the Government to consider this. But at the moment, I am under the impression that so long as these provisions of the Constitution are there, I do not think it is possible to make any reservation on the basis of sex.

One thing I want to make very clear. The hon. Member, Mrs. Geeta Mukherjee, quoted a lot of figures. In the beginning itself, I had made clear that whatever figures I have with me and whatever figures I have been quoting, are the figures only upto 1980. I do not have the figures for 1981 and I do not have the figures for 1982. If the hon. Member, with

regard to employment of women in a particular industry, is in possession of the latest figures, I am not in a position either to confirm or contradict because I do not have the figures at all. I collected these figures upto 1980 because the question is a general one. The question is about the declining trend in employment for women. That means in all the employments. The hon. Member wanted to know whether it is not a fact that there is a declining trend in employment for women in the public sector. I have got the figures, but these are only upto 1980. In 1977, the number of women in employment in the public sector were 12,52,000 and in 1980, 14,47,000......

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: What is the percentage? You come out with the percentage.

14.30 Hrs.

(SHRI R. S. SPARROW *in the Chair*)

Percentage. Come on to that.

SHRI VEERENDRA PATIL: I have already accepted that position. But the question that you have put is about the declining trend.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Jute Textile Coal. You say 'No.'

SHRI VEERENDRA PATIL: About textiles, I have already given the figures. In textiles, I tell you the number has gone up from 84,300 to 88,100. I have the figures only for a few industries. I do not have the fiigures for all the industries. About Jute I cannot say.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: What about jute?

SHRI VEERENDRA PATIL: So far as jute manufacture, hemp and textile industry is concerned, I do not have separate figures for these industries but the employment is very little.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Does not even come in for percentage calculation

SHRI VEERENDRA PATIL:—

Year	No. of women employed.
1976	7,900
1977	7,200
1978	6,900
1979	7,200
1980	7,200

The number engaged is very little.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : No.

SHRI VEERENDRA PATIL: I would like to make it very clear that unfortunately I have got figures only up to 1980. I do not have figures for 1981 and 1982.

Therefore, I can collect figures. The Hon. Member has put some questions. She wanted to know the number of employed women in public sector, private sector and in Government Departments. I have to collect figures from all these sectors. Then it will be possible to compile these figures. That is why, I am not in a position to say anything about the figures beyond 1980. I will collect the figures. Then only I will be in a position to place the figures on the Table of the House.

श्रीमती विद्या चन्नुपत्ति (विजयवाड़ा): सभापति जी, आज हम सारी की सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है क्योंकि हम सरकार और सदन का अटेन्शन इस ओर खींचना चाहते हैं कि महिलाओं की क्या प्राब्लम हैं। आज आप यहां ही देख लीजिए कि हम महिला संसद सदस्यों की संख्या बहुत कम है। आप आफिशियल गेलरी में भी देखिए कि वहां भी केवल एक ही महिला है। इसलिए हम कहते हैं कि आज महिलाओं की हालत कैसी है।

महिलाएं आज दो काम कर रही हैं। एक तो वे घर को सम्भाल रही हैं, पति का काम भी वे देखती हैं, बच्चों का पालन करती हैं। घर में जो काम होता है उसको कर के वे घर की फाइनेंशयल मदद करने के लिए एम्पलायमेंट में भी जाती हैं। हमारे पतियों की आमदनी सफीशियेंट नहीं होती है इसलिए हम यह

सोचती हैं कि हम अपने पतियों की भी कुछ मदद करें। इसलिये हम नौकरी भी करती हैं ताकि हम अपने घर की मदद कर सकें, अपने परिवार और पति की मदद कर सकें।

आज के संसार में हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे फिगर दिए हैं। वे कहते हैं कि हमने कुछ टेक्नीकल इंस्टीच्युशंस, आई० टी० आई० और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्युशंस खोले हैं। ये सब फिगर उन्होंने दिये और कह दिया कि वे हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, यह मैं मानती हूं। लेकिन जितना हमारा परसेन्टेज है, उसके हिसाब से इस देश में काम नहीं हो रहा है। यह हम कहना चाहती हैं। आम जनता में हमारा परसेन्टेज 50 परसेन्ट है। आपने कहा कि सारे देश में दो नेशनल वोकेशनल इंस्टीच्यूट्स बनाये हैं और चार के लिए आप और रिकमण्ड कर रहे हैं इतने बड़े देश में इतने इंस्टीच्यूट्स महिलाओं के लिए क्या सफीशियेंट हैं, इसको आप सोचिये। हम यही कहना चाहती हैं कि महिलाएं काम करने के लिए आगे आना चाहती हैं। दोनों को काम देना चाहिए। जैसा कि प्रमिला जी ने कहा है कि महिलाएं चाहे अनपढ़ हों या पढ़ी लिखी हों, उनके काम के बगैर गुजारा नहीं होता है। इसलिए उनको भी काम देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के लिये एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज बनानी चाहिएं। इस तरह के काम ढूंढ़े जाने चाहिएं जो महिलाएं घर में बैठकर कर सकें। इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। अगर सिर्फ कागज पर यह कार्य किया गया है तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि कि इन कार्यों को इंप्लीमेंट कराया जाए। एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज, काटेज विलेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास करना होगा। 90 प्रतिशत महिलाएं घर में रहती हैं इसलिए उनको घर पर ही काम देने के बारे में आप सोचिए और उनके द्वारा बनाए गए फिनिश्ड गुड्स के मार्केटिंग की व्यवस्था कीजिए। आप सारी महिलाओं को जाब नहीं दे सकते लेकिन घर में काम दे सकते हैं। हमारी प्रधानमंत्री भी भी महिला होने के नाते अपने भाषणों में इस बात को कहती हैं। वे महिलाओं के लिए अधिक चिंतित हैं। लेकिन उनके द्वारा बताए गए कार्यों को इंप्लीमेंट करने वाले मर्द लोग हैं। इसीलिए उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि महिलाओं को घर पर काम दिया जाना चाहिए और फिनिश्ड गुड्स की मार्केटिंग की व्यवस्था केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले। यह कार्य बहुत आवश्यक है।

टेक्नीकल एजूकेशन के बारे में बताया है कि आई० टी०आई० और पालेटेक्नीक कालेजेज हैं। लेकिन यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद भी महिलाओं को काम नहीं मिल पाता है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई जगहों पर यह भी बताया गया है कि महिलाएं मेटरनिटी लीव लेती हैं इसलिए उनको काम नहीं दिया जाता। यह बड़े अफसोस की बात है। मातृत्व महिलाओं को प्राकृतिक देन है। यह मर्दों के लिए नहीं है। इसके लिए संस्थाओं को तीन महीने की छुट्टी तथा अन्य सुविधाएं देनी पड़ती हैं। इस आधार पर महिलाओं को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। महिलाओं के लिए मातृत्व प्राकृतिक देन है। इसके बारे में सहानुभूति से विचार करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर्स पढ़ी-लिखी और अनपढ़ दोनों तरह की महिलाओं के लिए इंट्रोडयूज किये जाने चाहिए। वहां कम्पलसरी क्रेशेज होने चाहिए। कुछ जगहों पर तो क्रेशेज होते हैं लेकिन सब जगहों पर नहीं होते हैं। जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां कम्पलसरी क्रेशेज होने चाहिए। आपको यह मानना पड़ेगा कि आजकल महिलाएं ज्यादा पढ़ी-लिखी हो रही हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। मंत्री जी ने तो कह दिया कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन जब सिलेक्शन होता है उस वक्त ह्यूमेनीटेरियन ग्राउन्ड्स पर कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं। जब भी महिलाएं

इन्टरव्यू के लिए आएं तो उनके साथ सिलेक्शन में सहानुभूति होनी चाहिये। आप यह न सोचिए कि उनको मेटरनिटी लीव देनी पड़ेगी इसलिए काम देना मुश्किल है। इन्टरव्यू में महिलाओं को प्रायोरिटी मिले, इसके लिए तो गवर्नमेंट दे सकती है। इसके लिये स्पेशल इन्टरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। जब तक महिलाओं को ज्यादा एम्पलायमेंट नहीं मिलेगा उनकी समस्याएं साल्व नहीं हो सकती हैं। आजकल हर रोज अखबारों में महिलाओं के बारे में डाबरी डेथ्स और एट्रोसिटीज के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसका कारण यह है कि महिलाएं इकॉनामीकली सेल्फ सफिशियेन्ट नहीं हैं। वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। जब तक हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक समाज में सुधार नहीं आ सकता। एम्पलायमेंट फैसिलीटीज इन्क्रीज करने के लिये सरकार को सहानुभूति से सोचना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री जी के भी अभारी हैं क्योंकि वे हमारी बहुत मदद कर रही हैं। मंत्री महोदय भी मर्द हैं इसलिए वे हमारी अवश्य मदद करें, हमें कुछ सहारा दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीया सदस्या ने भी महिलाओं के बारे में अनुरोध किया है कि गवर्नमेंट को सहानुभूति दिखानी चाहिये, उनसे मैं सहमत हूं। गवर्नमेन्ट पूरी सहानुभूति से उनकी समस्याओं को देख रही है और आगे भी देखेगी। बहुत से प्रोग्राम्स के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, अब फिर दोहराना नहीं चाहता हू। माननीया सदस्या ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिये अनुरोध किया हैं। हमने स्टेट गवर्मेन्ट्स को लिख दिया है कि महिलाओं के लिये जितनी आई० टी० आई० हैं, वे काफी नहीं है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। इसके लिये फिर से लिखेंगे। स्वीडीश एड से भी हमने एक वोकेशनल ... **(व्यवधान)**

श्री रामप्यारे पनिका : सेन्ट्रल सेक्टर में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम लें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सेन्ट्रल सेक्टर में नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट रीजनल ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट आदि हैं। इसी प्रकार चार ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट हम और शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि माननीया सदस्या ने कहा है, हर महिला को नौकरी देना मुश्किल है। इससे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए मुश्किल हो जायेगा। एम्पलायमेन्ट के बारे में महिलाओं को सोचना चाहिए। उनको ऑरगेनाइजेशन, सोसायटीज, काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए। और खादी ग्रामोद्योग के बहुत से प्रोग्राम्स हैं उनके लिहाज से सोसायटीज बना कर के उनके जरिए चालू कर के देहात के अन्दर बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं।

मैं कहना चाहता हू कि हम पूरी हमदर्दी से सोच रहे हैं, हर मिनिस्ट्री में महिलाओं के लिये प्रोग्राम्स और कार्यक्रम हैं और हमारी स्कीम में भी है, और इसको बढ़ाते जायेंगे

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : नेशनल कमीशन आन वीमेन्स के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI: Mr. Chairman, I am shocked and distressed at the statement made by the hon. Minister in reply to the Calling Attention Notice given by us. It reflects the apathy and uncncern of our society to women. Instead of fully sharing the views of the Hon'ble Members who spoke on the Calling Attention Motion, statement has watered down the real issues. While replying to the points raised by my colleagues, the Minister has added very little and he has relegated the whole issue and instead of doing something good for the cause of women, he has shifted the responsibilities on women themselves. Now, what is there in the Statement? I will try to be as brief as possible.

First, he has said that the Government is aware of the apprehensions expressed by the Women's Organisation about the unsatisfactory employment position of women. He has said that in most of the industries women's

employment is increasing and the decline is very small. Then, he has said that there is retrenchment. But he does not know who are being retrenched men or women .

He has also said that it is the States' responsibilities for the State sectors. Then he says that the placement of registered unemployed women compared to men is low. But the difference is forgivable, because women are also employed by the private persons outside Employment Exchanges Channel. It is said that women are being trained in the training institutions. But the percentage he does not give. Then, he says about the Equal Remuneration Act, setting up of Advisory Committee, etc. They have done everything, they have done enough and everything is fine and it is only some silly Women's Organisations which are making a great fuss over nothing. He seems to say that he has nothing to do and the women have to put up with the problems.

Now, I want to know the understanding of this Ministry. Do they really feel that the apprehensions regarding the employment position of women in the country are unfounded ? That the position is satisfactory ? In this connection, I would like to quote from Blue Print of Action Points and National Plan of Action for Women". It was prepared by the Ministry of Social Welfare in Consultation with other relevant Ministries including his ministry. It says like this.

> "The Constitution guarantees equality of opportunity in matters relating to employment and directs the State to secure equal rights to an adequate means of livelihood, equal pay for equal work and just and humane conditions of work. The impact of transition to a modern economy has resulted in the exclusion of an increasing number of women from active participation in the productive process and only a limited recognition of their contribution and ability to contribute".

Now, I would like to ask the Minister whether he is in agreement with this statement.

Let us see the acltual position according to 1971 Census, 52.5% male pcpulation are employed, that is, 149 million people are employed out of total 283 millions. As againts this, only 13.8% of female population are employed, that is, only 34 million are employed out of 364 millions. Even if we concede to what the Government says that the decline in womens participation ratio from 1961 to 1971 Census, had been due to change in the definition of workers, even then there was a sharper decline in the female participation rate as compared to male; i. e. the male decline was from 57.1% to 52.53%, while for women, it was from 28% to 13.8%.

Now, the 1981 census has come. What are its findings? They have done a very good thing. They have carefully attempted a face-saving on this participation ratio of women by liberalizing the definition of 'worker'. That has included anybody who as worked any time during the year. But, unfortunately, even then the work participation rate for women has been on more than 20.8%, still 7.15% less than that under the 1961 Census. It means, as pointed out in Statesman' of 18th February last, that in the 20 years during which the female population has shot up by 112 million or 55%, the female work force has increased in absolute numbers by less than 9 million or 15%, resulting in a solid decrease of a full quarter in the participation rate, from 28% to less than 21%. It is less than 21% in 1981.

According to 1981 Census, out of the 66.3 million working women, only 45.9 million are 'main' workers and 20.3 million or as much as 30% are marginal workers, while the male marginal workers are only 3%. As against 51% of males, only 14% of females have full time jobs. Others are marginal.

As against 48.8% of male population, the percentage of female non-workers is more than 79%. That shows the extent of economic independence we women have in this independent country.

Now about the agricultural sector, because that shows how worthwhile economic opportunities are fast vanishing for women everywhere. Most of our work force is in agriculture, and the percentage of women workers remains more or less here. In agriculture, their percentage remains more or less the same. But female cultivators dwindled from more than 55% in 1961 to 33% in 1981. That means women are relegated more and more to the

position of agricultural labourers. Their absolute numbers are starker. While the number of male cultivators has gone up from 63.6 million in 1961 to 76.2 million in 1981, the number of women cultivators has become less than half in the 20 years i. e. from 31.8 million to 15.1 million. So, the picture is gloomy, to say the least.

The female-male worker ratio in 1911—it has come out in "Times of India" --was 525:1000 workers. In 1951 it came down to 408:1000; in 1971, to 210:1000. The small increase in 1981 has, at best, been only marginal.

An ICSSR research showed that even in Government service, the index of women's participation fell from the base 100 in 1901, i. e. at the start of the century, to 96 in 1971. There is no wonder that the Minister's statement is apathetic. Only 6% of women employed, work in organized industry. They are being driven out of employment in this sector. In Jute, what is the position? I should say only this that in 1944, 14 per cent women were there out of the total workforce in jute mills. By 1972, it came to less than 4 percent. Now, there is no percentage. They have practically wiped out every women in jute mills.

In textiles, as pointed out in *Economic & Political Weekly*, in 1951, women cynstituted 25 per cent of total workforce, in Bombay. Today, they constitute just about 5 per cent. In Bombay textile mills, he said, from 40,000, now they have come down to mere 5000. According to the survey of his Ministry which came out in *The Hindustan Times* dated 1. 1. 79.—that survey was on mica, cotton, jute, silk and food processing industry—the employfment of women is on the decline. In the silk textile units under survey, the number ot women workers came down from 3129 in 1970 to 2465 in 1976-77—a decline of 21 per cent in five years. Now, there are big units in Bombay—as Shrimati Prarnila Dandavate said—where in 10-12 years not a single women has been employed.

Now what is the position in plantation? In Plantations in plucking, picking and weeding, women are as efficient as men and even more efficient than men. In tea plantations upto 1971 women outnumbered men, but that position had been reversed in 1972 when women became fewer by 25,000 than men and the downward trend continues and has been accelerated. The same happened in coffee also. Now I should like to ask a question from the Minister. Whether the incidence of progressive diminishing of maternity claims in plantations is the end result of the threat of retrenchment from service. Is the government prepared to set up a committee of enquiry to find out what is happening there?

Regarding tobacco, coir, *bidi* ,etc. I am quoting from Sixth Five Year Plan—Chapter on Women and Development. Issays as follows:

> Modernization of traditional occupations of women such as spinning and weaving, match-making, coir, cashew, rural marketing, agriculture, animal husbandry and fishery, etc. would be selected and would include simultan cous Development of skills for alternative employment for them.
> Then it further say as follows:
> "The impact of new projects on women's employment will be monitored."

I want to know from the Minister what he is going to do for this?

What is happening in tobacco. Shrimati Dandavate has referred to it, there must have been a confusion. In tobacco, due to import of threshing machines, about one lakh women workers face retrenchment. The Minister said that this is necessary because of export, etc. That is not the case. The foreign buyers don't want machine-made things; they want hand-made things. Still import of threshing machines are permitted by the Central Government despite repeated representations to his Ministry and even two representations to the Prime Minister. In Andhra Pradesh, in one establishment, at Anabarti, 6000 women have been driven out, that is in Chirala Factory and perchur Depot. I would like to know how many licences have been issued for importing threshing machines? In coir industry also, I would like to know how many licences have been issued; whether the government is going to permit the import of machinery for mechanisation? How many licenses are being given to mechanise coir industry which again endangered one lakh women employees?

What has happened in bidi industry? Lakhs of women are employed in bidi factories. Now these factories have been closed

and the bidi industry has gone home-made in order to avoid application of statutory laws. What steps does the Government propose to take to stop this and protect women from these factories?

About mines, according to the Indian Labour Journal—Apil, 1980, the percentage of employment of women workers in mines is systematically going down. In 1951, it was 20 per cent, in 1961 it was 15.8 percent and in 1971 it came down to 11.9 per cent. Shrimati Dandavate has already given the figures that from 30,000 women in 1973, the figure has gone down to 12,000 in 1982. I do not know what is the position in 1983. We see that the public sector is leading the way in systematically retrenching women.

The continued discrimination against female workers in the BCCL is going to erdminate women totadly from our coal mines. The Baveja Committee Report declared more than 50,000 women wagon loaders as surplus without providing them substitute employment. There is the revealing case of Ekra Vasudebpur colliery, about which we wrote letters also, where BCCL is party to a tripartite settlement employing all 25 male ex-contractor's labour while throwing out all 27 female workers. Even the invervention of the Union Labour Minister, Shri Bhagwat Jha Azad, could not get them their employment back on humanitarian grounds let alone as of right. There is a copy of the tripartite settlement with me. I may be given permission to lay it* on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: We will examine it.

SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI: The question is: What the Government is going to do? Since this is a public sector undertaking, should we take it that the Government itself has started making discrimination against women as policy?

Why is it that women are not being taken more and more in open cast mining, which is being expanded as a policy and which is a surface work? Shell picking is very necessary in mechanised loading to avoid mixing of stones with coal, which is very much detrimental to boilers, blast furnaces, etc. Has the Ministry any course of action in regard to open cast mines and also for shell-picking for employment of women?

I would like to ask some more questions—Whether HMT, which is a leading public sector undertaking, is transferring its production to women in household sector or to ancillaries where conditions are far worse than in HMT factories? What steps does the Government propose to take to arrest the growing displacement of women from public sector undertakings industry-wise in the industry also?

About the National Plan of Action, there were specific recommendations for finding out areas of employment, review mechanism, follow-up action, data collection, monitoring etc. I want to know: what steps are being taken to implement this National Plan of Action for Women? Has any review mechanism been set up?

He has not answered as to why the Government has delayed setting up commission on women,

Another question is whether it is a fact that the Government is advocacting relaxation of protective laws for women. Why not the Government come forward with a plan of subsidies, incentives and State care for children taking the issue as a social burden recognising motherhood as a national responsibility? Will the Government do it in the very near future not as 'concession' to so-called 'handicap' of women but as necessary provision to ensure equal opportunity proclaimed by Constitution?

In this action plan and others, there was a recommendation to allocate money, that is, 25 per cent of allocation for women employment generation. Will there be explicit mention of women as a target group in all plans and programmes for employment generation with earmarking of financial allocations, staff support and specific monitoring arrangements? So, these are the questions and I welcome the concern of all our colleagues here and I would like and demand a full-scale discussion on the Floor of this House regard-

* The Speaker not having Subsequently accorded the necessary permission the document was not treated as laid on the Table.

ing problems of women, especially employment of women.

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, most of the questions that have been put by the hon. Member just now are only repetition because all those questions have been put by other Members also. But I am happy that through this discussion their purpose is served. They wanted to focus the attention on the problem of employment for women; so, that purpose is served. I have also made it very clear that so far as we as Government are concerned, we are very much concerned about the employment opportunities for women. We are taking steps and we never claim at any time that whatever steps we have taken and whatever achievements are there are to our satisfaction. We have to go a long way. I have already made it very clear to the hon. Members and repeatedly hon. Mrs. Dandavate wanted to know whether Government of India is going to constitute a National Commission on Women. I am not in a position to say anything because I am told the concerned Ministry is the Social Welfare Ministry. So, it is for the Social Welfare Ministry to consider this point. I do not know whether that proposal is before their consideration or not. Therefore, since it is not a matter concerning my Ministry, I am not in a position to say anything about that.

Repeatedly, the hon. Member was saying that employment opportunities in public sector are going down but I have replied to that question. I have said that in public sector the women's employment is going up and I have quoted the figures also. I have the statement before me but it is not correct to say that the employment opportunities in public sector are going down.

So far as the employment opportunities for opencast mines are concerned, in opencast mines ladies are allowed to work but only in underground mines ladies are prohibited to work. I do not want to say anything more but I want to emphasise again that if we vigorously implement the 20-Point Programme-there are so many programmes particularly for rural areas and 80 per cent of our peoble live in rural areas—if we pursue those programmes and take necessary action to implement them in letter and spirit, such as NREP, IRDP, Self-Employment Programme, Khadi and Village Industries Programme and so many other programmes which are meant for providing employment, then I think to a great extent it will be possible for us to solve this problem. I want to assure the hon. Member that I would take up this matter. So far as creating more employment opportunities for women are concerned; I would take up this matter with the State Governments. I will personally write letters to the State Governments and I will impress upon them to the urgent need of taking necessary steps for dealing with this point.

14.50 Hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to set up a coach Factory at Subedargaij, Allahabad

श्री कृष्णप्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उत्तर भारत के जनपद इलाहाबाद में रेल मंत्रालय द्वारा एक कोच फैक्ट्री लगाने हेतु शंकरगढ़ सूबेदार गंज आदि स्थानों का सर्वेक्षण परसाल हुआ था। शंकरगढ़ में ब्राडगेज लाइन है किंतु मीटर गेज लाइन नहीं है। शंकरगढ़ में हजारों एकड़ पथरीली भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी जिस पर खेती भी नहीं होती तथा मूल्य भी नाम मात्र का है, किंतु रेल मंत्रालय ने बाद में सूबेदार गंज इलाहाबाद का स्थान तय किया क्योंकि यहां थोड़े खर्चे में मीटर गेज लाइन रामबाग इलाहाबाद में मीटर गेज लाइन से जोड़ी जा सकती है और सूबेदार गंज स्वतः ब्राड गेज लाइन पर है। सूबेदार गंज में जमीन भी उपलब्ध है जो कि सौभाग्य से रेल विभाग की है।

इलाहाबाद में इस कोच के कारखाने के कायम किए जाने की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई किंतु कोच फैक्ट्री की स्थापना में देरी होने से तथा कभी-कभी यह सुनाई पड़ने से कि अब यह कोच फैक्ट्री अन्यत्र स्थापित होगी इलाहाबाद में बड़ी चिंता व्याप्त हो गई है।

मेरा रेल मंत्रालय से निवेदन है कि अविलंब सूबेदार गंज इलाहाबाद में प्रस्तावित कोच फैक्ट्री को लगाने का निर्णय लेकर के उसे शीघ्र से शीघ्र स्थापित करें।